PC based multi-purpose counter machines have been installed at Parliament Street HQ, Delhi GPO and Connaught Place PO in Delhi and three POs in Bangalore on an experimental basis.

Efforts are underway to computerise in HPOs of Delhi Circle in the first instance. Computerisation of PLI has been introduced in Calcutta and Bangalore, it is proposed to extend similar computerisation in a few other circles in the next financial year.

The question of computerisation of HPOs accounts is under examination. As regards induction of suitable technology for introducing satellite mail etc., various alternate technologies and modalities for introducing satellite mails are under examination for taking a final decision in this regard. Introduction of computerised MIS/ Data transmission system is also under examination.

Recommendation of Committee on Indo-Nepal Border

911. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether any Master Plan has been recommended by the Committee on the Indo-Nepal border;

(b) if so, what are the main features of the Master Plan to check the floods in the Indo-Nepal border; and

(c) whether Government propose to implement the same?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI MANUBHAI KOTADIA): (a) to (c) The Standing Committee on inundation of problems at border which met in January, 1991 has recommended preparation of a Master Plan for flood management covering both short and long term measures to check the floods at the border.

Prime Minister on Indo-Sri Lanka accord

912. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister has stated that India has fulfilled its obligations under the Indo-Sri Lanka accord, but Sri Lanka has not implemented any provisions so far;

(b) if so, what are the main obligations which Sri Lanka has not so far fulfilled; and

(c) whether any direct talks are likely to be had by Prime Minister with the Sri Lankan President on the implementation of the accord?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): (a) In an interview with Sri Lankan journalists the Prime Minister stated that Government of India has fulfilled all its obligations and that it is for the Sri Lankan Government and the Tamil People there to implement the rest of the accord, if it has not been implemented.

(b) On the basis of the devolution package, contained in the Indo-Sri Lanka Agreement, the Sri Lanka Government enacted the 13th Constitutional Amendment (Nov. 1987) and consequential legislation. It devolves on the Sri Lanka Government to fully implement it, in letter and spirit.

(c) No, Sir.

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना

913. श्री अजीत जोगी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1991 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश की कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित पडी हैं ;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लम्बित हैं तथा उन्हें मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इनमें कुछ परियोजनाएं पन्ना और दमोह जिलों के लिए भी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर कितना व्यय होने तथा इनसे कितने क्षेत्र की सिंचाई होने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री साथ में जल भूतल परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री मनुभाई कोटाड़िया) :(क) और (ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

(क) उन परियोजनाओं की स्थिति जिनका तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है

क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा होने की तारीख	स्थिति
1	2	3	4	5
i. बृहद परियोजनाएं				
1.	बारगी बहु-प्रयोजनी	6/83 1/89	9/89	राज्य को पर्यावरणिक स्वीकृति प्राप्त करनी है ।
2.	पेंच दिक परिवर्तन	8/85 8/88	10/88	हाल ही में, 11/90 को पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं ।
3.	महान	7/82 6/83	6/83	राज्य द्वारा अनुमान संशोधित करना तथा जलग्रहण क्षेत्र की उपचारी योजना प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।
4.	मान	11/82 1/84	12/86	राज्य द्वारा अद्यतन लागत अनुमान प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।
5.	ओंकारेश्वर बहु-प्रयोजनी	4/86 5/88	10/88	केन्द्र को पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्रस्तुत न करने के कारण आस्थगिता ।
ii. मध्यम परियोजनाएं				
1.	गेज	6/84	9/84	राज्य द्वारा अद्यतन लागत अनुमान प्रस्तुत करना तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना अपेक्षित है ।
2.	माहुअर	7/84	9/84	राज्य द्वारा अद्यतन लागत अनुमान प्रस्तुत करना तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति और वन स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है

1	2	3	4	5
3.	बाह	5/87	4/88	राज्य द्वारा अद्यतन लागत अनुमान प्रस्तुत करना, राज्य वित्त विभाग की सहमति और वन स्वीकृति की प्रति प्राप्त करना अपेक्षित है।
4.	बारचार	10/84	11/85	टिप्पणियों पर राज्य की अनुपालना तथा अद्यतन लागत अनुमान हाल ही में प्राप्त हुआ है।
5.	सुतियापट टैंक	6/89	11/89	अन्यों के साथ-साथ विस्तृत पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजनाएं प्रस्तुत न करने के कारण आस्थगित।

(ख) केंद्र के पास शेष परियोजनाओं की स्थिति

क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	स्थिति
1.	**बृहद परियोजनाएं**		
1.	बाणसागर यूनिट–II	7/88	हाल ही में, संशोधित रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
		1/91	
2.	बारगी दिक्परिवर्तन	4/85	हाल ही में, अनुपालना प्राप्त हुई है। राज्य द्वारा पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है।
		11/90	
3.	केलो सिंचाई	5/88	राज्य द्वारा बांध अभिकल्प, सिंचाई आयोजना, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजनायें तथा पर्यावणिक एवं वन मुद्दों को हल करना अपेक्षित है।
4.	मोंगरा सिंचाई	5/89	राज्य द्वारा तकनीकी मुद्दों को हल किया जाना तथा पर्यावणिक एवं वन स्वीकृति का प्रबंध करना अपेक्षित है।
5.	महानदी	10/83	राज्य द्वारा पर्यावणिक तथा वन स्वीकृति का प्रबंध करना अपेक्षित है।
		2/90	
6.	सिंघ सोपान-दो	6/79	आशोधित रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है।
		12/90	
7.	थनवार टैंक	12/89	इस परियोजना की तकनीकी-आर्थिक पूरी की जा चुकी है।